



**DHABRIYA
GROUP**

DHABRIYA POLYWOOD LIMITED

Regd. Office : B-9D(1), Malviya Industrial Area, JAIPUR-302 017 (Raj.) INDIA

Phone : +91-141-4057171, 4040101-105 | Fax : +91-141-2750814

E-mail : info@polywood.org | Website : www.polywood.org

CIN : L29305RJ1992PLC007003

Ref: BSE/2020-21/51

Date: 05.02.2021

To,
The General Manager
Department of Corporate Service
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code - 538715

Dear Sir,

Subject - Intimation of publication of Notice of the Board Meeting scheduled to be held on Saturday, February 13, 2021.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed is the copy of notice of the Board Meeting, published in the following newspaper:

- The Indian Express (English) on February 05, 2021
- Business Remedies (Hindi) on February 05, 2021
- Nafa Nuksan (Hindi) on February 05, 2021

Kindly disseminate the information on the official website of the exchange for the information of all members of the exchange and investors.

Yours faithfully,

For DHABRIYA POLYWOOD LIMITED



Sparsh Jain
Company Secretary & Compliance Officer
M No. A36383

For Your Information...

Market Cap Of All Listed Companies in Indian #StockMarket In Rs.

15 Jan 2015: 100 lakh cr

16 Mar 2017: 120 lakh cr

25 Oct 2017: 141 lakh cr

05 Nov 2020: 162 lakh cr

07 Dec 2020: 181 lakh cr

04 Feb 2021: 200 lakh cr

Source: BSE

Compiled by Nafanuksan Research

विचार सागर

“सूत कागज की उस नाव की तरह होता है जो अधिक दूर तक नहीं जा पाती।”

- पी.सी. वर्मा

“अपनी प्रशंसा सुनना हर व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और इसी कमजोरी के कारण चापलूसी जन्मी है।”

- के.आर. कम्मलेव

Thoughts of the time

Friendship is almost always the union of a part of one mind with a part of another; people are friends in sports.

- George Santayana

राजस्थानी कहावत

खसम री काण ने रामजी री आण खसम का मान और रामजी की कसम

- औरत के लिए पति की मर्यादा व रामजी की कसम दोनों महत्वपूर्ण होती है।
- जो सभी मर्यादाओं का समान रूप से पालन करता हो।

-स्व. विजय दान देथा

साधार : रूपायन संस्थान, बोरूदा

बाजार

बीएसई सेन्सेक्स	50614	358
एनएसई निफ्टी	14895	105
इंडिया विक्स	23.12	-0.63
एनसीएक्स कॉमडेक्स	10548	-27
एनसीडीएक्स एपीडेक्स	1172	11
डॉलर (रुपये में)	72.95	-0.01
यूरो (रुपये में)	87.49	-0.07
कच्चा तेल (बास्कर/बिस्तर)	56.16	0.56
लंदन बेंट क्रूड (बास्कर/बिस्तर)	57.90	0.70
एल्यूमिनियम (बास्कर/टन)	1958	-
तांबा (बास्कर/टन)	7755	-
निकल (बास्कर/टन)	17756	-
टिन (बास्कर/टन)	25000	-
जिंक (बास्कर/टन)	2539	-
सोना (बीएस/औंस)	1836	-8
सोना (MCX, रु. प्रति 10 ग्राम)	47340	-410
चांदी (MCX, रु. प्रति किलो)	67625	-940

यह भाव शाम 6.00 बजे तक के हैं।

शुक्रवार के चौघड़िए

सम्वत् 2077 माघ बुदी अष्टमी राहुकाल : प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक सूर्योदय: 7.14 बजे और सूर्यास्त : 6.07 बजे

प्रातः 7.14 से 8.36	चर
8.36 से 9.58	लाभ
9.58 से 11.20	अमृत
11.20 से 12.41	काल
12.41 से 2.02	शुभ
2.02 से 3.24	रोग
3.24 से 4.45	उद्देग
4.45 से सूर्यास्त 6.07	चर
रात्रि 6.07 से 7.46	रोग
7.46 से 9.24	काल
9.24 से 11.02	लाभ

‘डवलप किए जाएं छोटे इंडस्ट्रीयल एरिया’

बीकानेर/नि.सं.। जिला कलक्टर ने रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए कि जिले के नोखा, नापासर, लूणकरणसर एवं दंतोर क्षेत्र में छोटे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जाए। इन सभी स्थानों पर औद्योगिक एरिया विकसित करने के लिए 30 दिन में संपूर्ण प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ शुरुवार को राज कौशल के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाए तथा चर्चा कर यह निर्णय लिया जाए कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में किस तरह के कोर्स यहां प्रारंभ हो, जिससे बीकानेर के उद्यमी युवाओं को अपनी औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दे सकें। कलक्टर मेहता ने रीको प्रबंधक को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों का कचरा निस्तारण के लिए स्थान चिन्हित कर, डंपिंग यार्ड उपलब्ध करवाया जाए। स्थान चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।

मेहता ने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधक रीको इस बारे में खनिज अभियंता से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करें। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के आसपास अगर कोई पुरानी बंद खान हो तो उसे भी डंपिंग यार्ड के रूप में क्रियाशील करवाने की कार्यवाही अमल में लाएं। मेहता जिला उद्योग केंद्र की ओर से विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के तहत गठित जिला स्तरीय समिति तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय संवीक्षा समिति को बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बनाने हेतु गंगानगर रोड पर कोई राजकीय भूमि चिन्हित

करने की संभावना तलाशी जाए। साथ ही जिले के तीनों औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास अगर कोई बंद खान हो तो वहां भी डंपिंग यार्ड के रूप में कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। उन्होंने नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियन्ता संजय माथुर को निर्देश दिए की रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र घड़सीसर के पास सड़क का पेचवर्क होना है, यह कार्य फरवरी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए ताकि यहां यातायात सुगम हो सके। उन्होंने न्यास अभियंता को निर्देश दिए कि पानी की लाइन टूटने एवं सड़क पर घरों से पानी आने से क्षतिग्रस्त हुई सड़क को ठीक करवाएं। आसपास के लोगों को समझाइए कि पानी सड़क पर ना आए, इसके लिए नाली का ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचवीसिया द्वारा रोड के पेच वर्क का कार्य करवाने पर कहा कि शीघ्र ही पेचवर्क का कार्य पूरा होना चाहिए। न्यास द्वारा बनाई हुई नालियों में अगर कहीं मरम्मत की जरूरत हो तो वह भी ठीक करवाई जाए। जिला कलक्टर मेहता ने रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि करणी और बोधवाल औद्योगिक क्षेत्र में वेस्ट वाटर के

उपयोग के लिए एग््रीकल्चर विश्वविद्यालय के साथ एमओयू ककी। साथ ही क्षेत्र में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वे सभी इकाइयां इस योजना से जुड़े इसके लिए दोनों विभाग आपस में समन्वय कर सूची बना ले। बैठक में राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कछवा ने बताया कि इस कार्य के लिए एमडी रीको से बातचीत हो गई है और इस कार्य की डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बाबत 2 दिन पूर्व ही एमडी रीको से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जयपुर में बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने इस कार्य पर सैद्धांतिक रूप से अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है। जिला कलक्टर ने बताया कि खारा औद्योगिक क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही रानी बाजार और करणी इंडस्ट्रियल एरिया सहित तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय इकाइयों को फ्लाईऐश मिलेगा प्रार्थमिकता से : बैठक में बताया गया कि पावर प्लांट पर फ्लाईऐश उत्पन्न होती है, यह वर्तमान में अधिक मात्रा में बाहर के औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों को दी जा रही है, इस पर जिला कलक्टर ने महाप्रबंधक उद्योग मंजू नैन गोदारा को निर्देश दिए कि पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाईऐश का वितरण इस तरह से करें कि जिसके तहत स्थानीय स्तर पर जो जिन उद्योग इकाइयों को जरूरत हो उन्हें अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और बाहर के औद्योगिक इकाइयों को उसके बाद मिले, इसका संपूर्ण नोट बनाकर अगले 15 दिन में प्रस्तुत किया जाए।

औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ोतरी मिलेगी : परवाल

भीलवाडा/नि.सं.। कालानी एण्ड कम्पनी जयपुर के पी सी परवाल ने कहा कि इस बार केन्द्रीय बजट आधारभूत संरचनाओं के विकास पर केन्द्रीत करते हुए आया है। जिससे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे आधारभूत सुविधाओं के विकास होने से औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ोतरी मिलेगी।

इस बारे में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री भीलवाडा एवं टेक्सबा एंजिनियरिंग एंजिनियरिंग एंजिनियरिंग की ओर से वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट पर आयोजित वेबिनार में केन्द्रीय बजट पर व्यापक चर्चा करते हुए कहा कि काफी समय बाद स्टॉक मार्केट ने भी इस बजट को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। कोविड के कारण कुछ विपरित असर से रेवेन्यू प्राप्ति में कमी आने से आगामी वर्ष का रेवेन्यू डेफिसिट 1140576 करोड़ का होगा, जो कि देश की जीडीपी का 5.76% होगा। परवाल ने कहा कि वित्तमंत्री ने जीएसटी में इन्वेंटड इयूटी की विसंगतियां दूर करने के साथ जीएसटी प्रणाली में भी कई बदलाव किये हैं, जिससे उद्यमियों एवं व्यापारियों को कार्य करने में आसानी होगी। प्रत्यक्ष कर या आयकर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। महत्वपूर्ण परिवर्तन टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों में किया गया है, जिसमें पहले टीसीएस काटने की जिम्मेदारी विक्रेता की थी, उसे अब क्रेता की जिम्मेदारी कर दिया है। पेन नंबर नहीं होने की स्थिति में टीसीएस की दर 5% कर दी गई है। ऐसे व्यापारी जिनके पेन नंबर तो है लेकिन 2 वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए टीडीएस

नफा नुकसान

राजस्थान के निम्न केंद्रों पर उपलब्ध हैं

अलवर	: 9414261485
अजमेर	: 9929733155
भरतपुर	: 9667365632
बारा	: 9414009949
बिकानेर	: 9461780797
भीलवाडा	: 9414111700
बीकानेर	: 9829218705
चित्तौड़	: 9783923599
चित्तौड़गढ़	: 9414735097
देवली	: 9460591722
हनुमानगढ़ टाउन	: 9269094124
जयपुर	: 9460323908
जोधपुर	: 8107589141
जहजपुर	: 9636994402
जैतारण	: 9829390619
झंझुन	: 9887098514
कोल	: 9414178840
कानकरोली	: 9414933390
किशनगढ़	: 8209445053
कोटा	: 9214000265
कोटेश्वरी	: 9352885258
लासल	: 8876715835
नसीखद	: 7568692157
नागौर	: 9782375929
नवलगढ़	: 9983315255
पिपली	: 7737218404
पाली	: 7742427942
राजस	: 9166042391
श्रीगंगानगर	: 9414094108
सुरेन्द्रपुर	: 9928608845
टोंक	: 9414201309
उदयपुर	: 9829731366

आवास फाइनेंस लि0 का भरतपुर में शुभारम्भ : होम लोन एवं मोरगेज लोन देने के लिये आवास फाइनेंस लि. का स्थानीय बजाज कम्पनी के ऊपर नुमायश रोड पर शुभारम्भ हुआ। इस ब्रांच का उद्घाटन अनीश दिक्षित आवास फाइनेंस लि. के स्टेट हेड व भरतपुर ब्रांच के ब्रांच हेड नथन सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक अनुराग गर्ग, संजीव गुप्ता, दामोदर लाल गर्ग, वीरीसिंह, राजेन्द्र गोयल, सुधीर गुप्ता, प्रवीण जैन, सी.ए. भात भूपण, राजेन्द्र गर्ग, सी.ए. अतुल मित्तल आदि उपस्थित थे।

नेशनल/इंटरनेशनल

समिति निर्णय करेगी कि प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्र में कितने लोक उपक्रम रहेंगे

नयी दिल्ली/एजेंसी। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत मंत्रियों की समिति इस बात का अंतिम निर्णय करेगी कि प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को रखा जाए। सरकार ने बजट में विनिवेश/रणनीतिक विनिवेश नीति का प्रस्ताव किया। और चार क्षेत्रों...परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन और दूरसंचार; बिजली पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा बैंक...को रणनीतिक क्षेत्रों में रखा है। इन क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में केंद्रीय लोक उपक्रमों को रखा जाएगा। अन्य क्षेत्रों के केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीएसई) का निजीकरण किया जाएगा। नीति आयोग उन केंद्रीय लोक उपक्रमों की प्रारंभिक सूची तैयार करेगा जिसे रणनीतिक विक्री के लिये आगे बढ़ाया जा सके। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी का प्रबंधन करने वाला विभाग दीपम के सचिव ने कहा कि रणनीतिक निवेश नीति एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे निजी कंपनियों को मोटे तौर पर यह पता होगा कि कौन सी कंपनियां विक्री के लिये हैं। उन्होंने कहा, "कम-से-कम संख्या में कंपनियों को रखने का विचार है। मंत्री समूह (जीओएम) बनाया गया है जो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और संबंधित इकाइयों के प्रशासनिक मंत्रालयों के

मंत्रों इसमें शामिल हैं। समूह इस बात का निर्णय करेगा कि किसी खास क्षेत्र के लिये न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे कायम रखे जाने की जरूरत है।" पांडे ने कहा, "रणनीतिक क्षेत्रों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है...राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाएं, ऊर्जा और खनिज तथा वित्तीय सेवाएं।" यथासंभव कम संख्या रखने का मतलब है कि शेष का निजीकरण किया जा सकता है, या उसे बंद अथवा विलय या फिर अन्य केंद्रीय लोक उपक्रमों की अनुपंगी इकाई बनाया जा सकता है। पांडे ने कहा, "अतः सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया जा रहा है। इस नीति पर अगले कुछ साल तक काम होगा। इससे सरकार दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दे सकेगी। इससे निजी क्षेत्र के लिये संकेत मिलेगा कि सरकार के दिमाग में क्या है। पूंजी निर्माण के लिये यह जरूरी है कि निजी क्षेत्र की रूचि जगे।" सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष के लिये विनिवेश लक्ष्य संशोधित कर 32,000 करोड़ रुपये किया गया है। जबकि बजट में 2.10 लाख करोड़ रु. जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

किसान आंदोलन...

किसान आंदोलन में लोगों द्वारा मेडिकल कैम्प, लंगर, मुफ्त सामान आदि दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब वहां चार छोटी लाइब्रेरी बनाई गई है जहां कई भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं। फोटो : IANS

रोपवे को राजमार्ग मंत्रालय के दायरे में लाया गया

नयी दिल्ली/एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि रोपवे, केबल कार और फ्यूनिकुलर रेलवे (रस्सी या तार से चलने वाली रेलगाड़ी) अभिनव गतिशीलता समाधानों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री गडकरी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस कदम से देश के दूरदराज, दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उन्होंने कहा, "रोपवे, केबल कार, फ्यूनिकुलर रेलवे, बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। इससे दुर्गम इलाकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार तेज होगी।" उन्होंने कहा कि इससे दूरदराज के स्थानों से संपर्क स्थापित होने के साथ ही सड़कों पर भीड़ भी कम होगी। इस फैसले के बाद देश में गुणवत्ता और सुरक्षा पर जोर देते हुए विश्वस्तरीय रोपवे बनाए जाएंगे।